

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 10 दिसम्बर, 2005

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-2006 में निर्माणाधीन पूल्ड आवासों के निर्माण हेतु
घनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० -1320/111-2/05-41 (बजट)/2005 दिनांक 10 जुलाई, 2005, प्रमुख सचिव, वित्त के पत्र संख्या-1333(1)/XXVII(1)/05 दिनांक 20 अक्टूबर 2005 एवं आपके पत्र संख्या-3551/11बजट(मन) आयोजनागत/2005-06, दिनांक 24.10.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के प्रथम अनुपूरक मांग में निर्माणाधीन आवासों के निर्माण हेतु वर्ष 2005-06 के आय-व्यय में प्राविधानित घनराशि ₹० 60.00 लाख (₹० साठ लाख मात्र) की घनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वातन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत घनराशि का साख रीमा के आधार पर कोषागार से अहरण किया जायेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत घनराशि का व्यय चालू/निर्माणाधीन योजनाओं पर ही किया जायेगा तथा शासन की पूर्व अनुमति के बिना नई योजनाओं पर व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। कार्यवार आबंटित घनराशि की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी।

3- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर ही कार्य की स्वीकृत लागत की सीमा तक ही किया जाय।

4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट गैनुअल, वित्तीय हस्ताक्षरिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सहाय प्रधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-2 विस्तृत आगणनों पर राज्य अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उक्त स्वीकृत घनराशि का कार्यवार आबंटन कर वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को स्वीकृति के एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आवास के कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करके संबंधित को हस्तागत कर दिये जायेंगे।

7- यदि पुनः स्वीकृति के उपरान्त पुनः स्वीकृत की जा रही घनराशि का समयबद्ध रूप से उपयोग नहीं किया जाता है तो इसका समस्त दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का ही मानते हुए इसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही घनराशि का 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

प्रदीप सिंह रावत

9- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80 सामान्य- आयोजनागत-800-अन्य भवन-12 पुल्ले आधार योजना (चालू कार्य) आयोजनागत-00-24 कृता निर्माण कार्य के सुरुंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे खाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के आदेशसंख्या-87 /XXVII(2)/05 दिनांक, 28 दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

गददीय
(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

संख्या-245(1)/111(2)/04 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
- 3- अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग।
- 4- निजी सचिव, माओ मुख्य मंत्री जी को माओ मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 6- मुख्य अभियंता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोडा।
- 7- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
- 8- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3, उत्तरांचल शासन।
- 10- मार्ट बुक।

आज्ञा से,
प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।